ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या-35/201
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊ: जुलाई 05, 20

विषयः बलात्कार के अपराधों के विरूद्ध प्रभावी प्रतिरोध प्रदान करने हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018 के प्राविधानों व कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि महिलाओं/बच्चियों के विरूद्ध कारित अपराधों में बलात्कार/सामूहिक बलात्कार जघन्य अपराध है, जिससे समाज एवं न्याय व्यवस्था का विद्रूपित स्वरूप प्रकट होता है, साथ ह कानून-व्यवस्था की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार के अपराधों को अत्यन्त गम्भीरता स लेते हुए भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित दण्ड विधि में अपराध विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018 द्वार संशोधन करते हुए सजा को 07 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया गया है, इसी प्रकार 16 वर्ष या इसस कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार किये जाने पर सजा को 10 वर्ष से बढाकर 20 तक किया गया है। 16 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में सजा उम्र कैद के कारावास तथा 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार किये जाने पर अपराधी को आजीवन कारावास तथा 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने पर अपराधी को दोषसिद्ध होने पर उम्र कैद या मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

बलात्कार विषयक अपराधों में किये गये उपरोक्त संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं एवं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 **Protection Of Children From Sexual Offences Act-2012** (POCSO) की धारा-42 में भी अपेक्षित संशोधन किया गया है। जमानत के प्राविधान कठोर बनाये गये हैं। जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के समय पीड़िता अथवा परिवादी की उपस्थिति के प्राविधान आज्ञापक बनाये गये हैं। अपराधों की विवेचना 02 माह में पूर्ण किये जाने तथा अपराध का परीक्षण भी 02 माह में किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त अपराध विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018 की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

- इस प्रकार के अपराध घटित होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्र पंजीकृत कराकर समयबद्ध ढ़ंग से अधिकतम् 02 माह के भीतर विवेचना को पूर्ण कराकर आरोप पत्र मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे।
- अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र तथा उस पर सुनवाई की तिथि की सूचना पीड़िता अथवा परिवादी को उपलब्ध करायी जाये।
- अपराधों की गुणवत्ता पूर्ण विवेचना सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करायेंगे।

- प्रदर्शों को अधिकतम 02 दिवस के भीतर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्राप्त कराया जायेगा तथा प्रदर्श प्राप्त कराये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर आख्या प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विवेचना पूर्ण की जायेगी।
- दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018 के प्राविधानों का भली-भाँति अध्ययन कर जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों, जनपदीय संयुक्त निदेशक, अभियोजन, थाना प्रभारियों/थानाध्यक्षों तथा विवेचकों की जनपदीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें अध्यादेश के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु विस्तार से चर्चा करेंगे।
- परीक्षण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
- न्यायालय द्वारा निर्गत प्रोसेस का तामीला प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये, जिससे तामीला न होने के आधार पर स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018 के प्राविधानानुसार अपराधों की विवेचना, अभियोगों का परीक्षण निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत शीघ्रता पूर्वक पूर्ण कराया जाये।

आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए इस प्रकार के अपराधों के निवारण तथा अपराधियों को कठोर दण्ड से दण्डित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,
5/7/18
(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।

2

869 II
21.6.18

489
26/6/18

फैक्स/महत्वपूर्ण

संख्या-मा0स0- 90/6-पु0-15/2018

प्रेषक,

श्याम लाल यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

4
26.6

सेवा में,

ADG (Crime)

1- प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग
उ0प्र0शासन।

2- प्रमुख सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग
उ0प्र0शासन।

1
27.6

✓3- पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

A/20 DG
26-6-18

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 **लखनऊःदिनांक** 25 **जून, 2018**

विषयः- बलात्कार के अपराधों के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरोध प्रदान करने हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018(Criminal Law (Amendment) Ordinace,2018) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-1/3/2018-जेयूडीएल,सेल-एल(पी0टी0एल0) दिनांक 26-4-2018 एवं उसके साथ संलग्न आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018(Criminal Law (Amendment) Ordinace,2018) दिनांक 21-4-2018 की (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत सरकार द्वारा बलात्कार की घटनाओं के प्रति प्रभावी प्रतिरोध एवं सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश(यथासंशोधित)-2018 दिनांक 21-4-2018 प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश के अन्तर्गत बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्राविधान किया गया है जिसमें सजा की अवधि 7 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष किया जाना, 16 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार होने की स्थिति में बलात्कारी को 10 वर्ष से 20 वर्ष की कड़ी सजा जो सिद्धदोष अपराधी के शेष जीवन काल तक बढायी जा सकती है की व्यवस्था, 16 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में बलात्कारी को उम्र कैद की सजा, 12 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार होने की स्थिति में बलात्कारी को 20 वर्ष के कारावास की सजा जिसे सिद्धदोष व्यक्ति के शेष जीवन काल तक या मृत्यु तक बढाया जा सकता है, की व्यवस्था, 12 वर्ष से कम उर्म की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में सिद्धदोष व्यक्ति को उम्र कैद या फाँसी की सजा दिये जाने आदि कठोर प्राविधान शामिल किये गये है।

14(cr)

put up on file
29/6

(संजय सिंघल)
अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
27.6.18

29/6

सा.को.

SP Crime
27/6

पुलिस महानिरीक्षक (अपराध)
उ0 पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश लखनऊ

3- उक्त अध्यादेश द्वारा इन सारी कठोर दण्ड की व्यवस्था के अलावा आई0पी0सी0 यानी भारतीय दंड संहिता में भी संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत बलात्कार के मामले के केस की विवेचना दो माह के अन्दर पूर्ण की किये जाने तथा बलात्कार के मामलों का विचारण(Trial) दो माह में पूर्ण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अध्यादेश द्वारा बलात्कार के मामले में सबंधिंत सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अपील को निपटाने के लिए 6 माह की समयावधि विहित किये जाने तथा उक्त अपराधों के अभियुक्त की अग्रिम जमानत का प्रविधान समाप्त किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

4- आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018(Criminal Law (Amendment) Ordinace,2018) के दृष्टिगत उक्त प्राविधानों की पृष्ठभूमि में मा0 गृह मंत्री द्वारा ऐसे अपराधों की विवेचना, अभियोजन एवं विचारण तंत्र के क्षमता विस्तार एवं सुदृढीकरण, अवसंरचनात्मक व्यवस्था सहयोगी जनसंसाधन एवं विधि विज्ञान प्रयोग शालाओं आदि की समुचित व्यवस्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम के क्षमता निर्माण को मिशन मोड के अन्तर्गत तीन माह के भीतर कार्यशील कर दिया जाना है। इसके अतिरिक्त मा0 गृह मंत्री जी द्वारा उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार से अपने विचार/ सुझाव/सलाह/दिशानिर्देश से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है जिससे इस प्रकार के अपराधों के संबंध में एक सुदृढ विधि व्यवस्था बनायी जा सके ताकि महिलाओं और बच्चियों में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके।

5- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 गृह मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली उपरोक्त पत्र दिनांक 26-4-2018 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2018(Criminal Law (Amendment) Ordinace,2018) में उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करने के कष्ट करें। तथा संलग्न पत्र की अपेक्षानुसार अपना सुविचारित अभिमत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(श्याम लाल यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, अभियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(श्याम लाल यादव)
विशेष सचिव।

273 .... / पीजीएस / जीआई / 2018

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH

D.O.No. 1/3/2018-Judl. Cell-I(Pt.I

गृह मंत्री
भारत
नई दिल्ली-110001
HOME MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001

अ0सं0-90/दि0 15/18

22 Apr.

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव,
गृह, गोपन, [illegible]
कारागार एवं सतर्कता विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

Dear Shri Yogi Adityanath ji,

As you are aware, the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 has been promulgated on 21st April, 2018 to provide for effective deterrence against offences of rape. I am enclosing a copy of the said Ordinance.

2. The law as amended through this Ordinance provides for enhanced punishment for the offence of rape. The existing minimum punishment of 7 years imprisonment in rape cases has been increased to 10 years. The minimum punishment for the offence of rape of a girl child under 16 years of age has been increased from 10 years rigorous imprisonment to 20 years of rigorous imprisonment, extendable to imprisonment for rest of convict's life. Now, the punishment for offence of gang rape of a girl under 16 years of age is imprisonment for rest of convict's life.

3. Stringent punishments upto death sentence have also been provided in cases of rape of a girl child under 12 years of age. The minimum punishment for the offence of rape on a girl child below age of 12 years is 20 years imprisonment, extendable to imprisonment for rest of convict's life **or with death.** For the offence of gang rape of a girl child below 12 years, the minimum punishment will be imprisonment for rest of convict's life **or death**.

4. Apart from the above mentioned stringent punishments in the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure has also been amended. Now, the investigation of all cases of rape has to be mandatorily completed within two months. Further, trial of all rape cases has to be completed in two months. Six months time limit has been prescribed for disposal of appeals in all rape cases. The provision of anticipatory bail to the person accused of rape or gang rape of a girl under 12 years/ 16 years of age has also been done away with.

1066

VS(SHY)

pls speak

15/05/18

(भगवान स्वरूप)
सचिव
गृह विभाग
उ0 प्र0 शासन

861/SA/VIP/18

DS(P)/SOP15

4/6/18

(श्याम लाल [illegible])
विशेष सचिव
गृह विभाग
उ0 प्र0 शासन

Contd.on page 2/-

5. Further, the High Court or the Court of Sessions, before deciding the regular bail applications, will give notice of 15 days to the Public Prosecutor to appear for hearing of the application, where presence of a person authorized by victim shall be mandatory.

6. You would agree that in addition to the above stringent provisions in law, steps are required to be taken for capacity building of the investigation, prosecution and trial machinery. While the existing set up of investigation, prosecution and trial machinery needs to be strengthened, further capacity building at that level is also need of the hour. Setting up of Fast Track Special Courts to exclusively decide rape cases, sanction of additional posts for Public Prosecutors, office infrastructure and supporting manpower, adequate provisions for special forensic kits for rape cases and setting up of special forensic laboratories are absolutely essential at the ground level. In this regard, a scheme for capacity building to be implemented in a Mission Mode is to be launched in next three months, States/ UTs are also required to take immediate steps in the meanwhile to augment the capacities at these levels.

7. I would, therefore, request you to give appropriate directions and guidance to all concerned to take effective steps for strict implementation of the provisions of law and further measures to strengthen the investigation and prosecution machineries in your State, so as to instill sense of security among women, especially young girls.

With regards,

Yours sincerely,

26.04.18

(Rajnath Singh)

Encl.: as above

Shri Yogi Adityanath,
Chief Minister of Uttar Pradesh,
CM Office, Lal Bahadur Shastri Bhawan,
Lucknow-226001 (Uttar Pradesh).

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—18 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 2018/ वैशाख 1, 1940 (शक)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 2018/VAISAKHA 1, 1940 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 21st April, 2018/Vaisakha 1, 1940 (Saka)

THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ORDINANCE, 2018

No. 2 of 2018

Promulgated by the President in the Sixty-ninth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, 1872, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER II

AMENDMENTS TO THE INDIAN PENAL CODE

Amendment of section 166A.

45 of 1860.

2. In the Indian Penal Code (hereafter in this Chapter referred to as the Penal Code), in section 166A, in clause (c), for the words, figures and letters "section 376B, section 376C, section 376D,", the words, figures and letters "section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB," shall be substituted;

Amendment of section 228A.

3. In section 228A of the Penal Code, in sub-section (1),for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB" shall be substituted.

Amendment of section 376.

4. In section 376 of the Penal Code,—

(a) in sub-section (1), for the words "shall not be less than seven years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine", the words "shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), clause (i) shall be omitted;

(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:–

"(3) Whoever, commits rape on a woman under sixteen years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this sub-section shall be paid to the victim.".

Insertion of new section 376AB.

45 of 1860.

5. After section 376A of the Penal Code, the following section shall be inserted , namely:—

Punishment for rape on woman under twelve years of age.

"376AB. Whoever, commits rape on a woman under twelve years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine or with death:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.".

Insertion of new sections 376 DA and 376 DB.

6. After section 376D of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

Punishment for gang rape on woman under sixteen years of age.

"376DA. Where a woman under sixteen years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

Punishment for gang rape on woman under twelve years of age.

376DB. Where a woman under twelve years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine or with death:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.".

CHAPTER III
AMENDMENTS TO THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

Amendment to section 53.

1 of 1872.

7. In section 53A of the Indian Evidence Act, 1872 (hereafter in this Chapter referred to as the Evidence Act), for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB" shall be substituted.

Amendment to section 146.

8. In section 146 of the Evidence Act, in the proviso, for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D", the words, letters and figures "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB" shall be substituted.

CHAPTER IV
AMENDMENTS TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

Amendment of section 26.

2 of 1974.

9. In the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereafter in this Chapter referred to as the Code of Criminal Procedure), in section 26, in clause (a), in the proviso, for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB" shall be substituted.

Amendment of section 154.

10. In section 154 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1),—

(i) in the first proviso, for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D,", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA,section 376DB," shall be substituted;

(ii) in the second proviso, in clause (a), for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D.", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB," shall be substituted.

Amendment of section 161.

11. In section 161 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (3), in the second proviso, for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D,", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB," shall be substituted.

Amendment of section 164.

12. In section 164 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (5A), in clause (a), for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D,", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB," shall be substituted.

Amendment of section 173.

13. In section 173 of the Code of Criminal Procedure,—

45 of 1860.

(i) in sub-section (1A), for the words "rape of a child may be completed within three months", the words, figures and letters "an offence under sections 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB or section 376E of the Indian Penal Code shall be completed within two months" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), in clause (i), in sub-clause (h), for the figures, letters and word "376A, 376B, 376C, section 376D", the figures and letters "376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB" shall be substituted.

Amendment of section 197.

14. In section 197 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1), in the *Explanation*, for the words, figures and letters "section 376A, section 376C, section 376D", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB" shall be substituted.

Amendment to section 309.

15. In section 309 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1), in the proviso, for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C or section 376D of the Indian Penal Code, the inquiry or trial shall, as far as possible", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA or section 376DB of the Indian Penal Code, the inquiry or trial shall" shall be substituted.

Amendment to section 327.

16. In section 327 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (2), for the words, figures and letters "section 376A, section 376B, section 376C, section 376D", the words, figures and letters "section 376A, section 376AB, section

376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB" shall be substituted.

Amendment to section 357B.

17. In section 357B of the Code of Criminal Procedure, for the words, figures and letters "under section 326A or section 376D of the Indian Penal Code", the words, figures and letters "under section 326A, section 376AB, section 376D, section 376DA and section 376DB of the Indian Penal Code" shall be substituted.

45 of 1860.

Amendment to section 357C.

18. In section 357C of the Code of Criminal Procedure, for the figures and letters "376A, 376B, 376C, 376D", the figures and letters "376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB" shall be substituted.

Amendment of section 374.

19. In section 374 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

> "(4) When an appeal has been filed against a sentence passed under section 376, section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB or section 376E of the Indian Penal Code, the appeal shall be disposed of within a period of six months from the date of filing of such appeal.".

Amendment of section 377.

20. In section 377 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

> "(3) When an appeal has been filed against a sentence passed under section 376, section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB or section 376E of the Indian Penal Code, the appeal shall be disposed of within a period of six months from the date of filing of such appeal.".

Amendment of section 438.

21. In section 438 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:–

> "(4) Nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under sub-section (3) of section 376 or section 376AB or section 376DA and section 376DB of the Indian Penal Code.".

Amendment of section 439.

22 In section 439 of the Code of Criminal Procedure,

(a) in sub-section (1), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

> "Provided further that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence triable under sub-section (3) of section 376 or section 376AB or section 376DA or section 376DB of the Indian Penal Code, give notice of the application for bail to the Public Prosecutor within a period of fifteen days from the date of receipt of the notice of such application."; 45 of 1860.

(b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

> "(1A) The presence of the informant or any person authorised by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under sub-section (3) of section 376 or section 376A or section 376DA or section 376DB of the Indian Penal Code.". 45 of 1860.

Amendment of First Schedule.

23. In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, under the heading "I.-OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE",—

(a) against section 376,—

(i) for the entry under column 3, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
		"Rigorous imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine";			

(ii) the following entries shall be inserted at the end, namely:—

1	2	3	4	5	6
	"Persons committing offence of rape on a	Rigorous imprisonment for a term which shall	Cognizable	Non-bailable	Court of Session

	woman under sixteen years of age.	not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine.			

(b) after the entries relating to section 376A, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"376AB	Person committing an offence of rape on a woman under twelve years of age.	Rigorous imprisonment of not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.';

(c) after the entries relating to section 376D, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"376DA	Gang rape on a woman under sixteen years of age.	Rigorous imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

1	2	3	4	5	6
376DB	Gang rape on woman under twelve years of age.	Imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine or with death.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.”.

CHAPTER V

AMENDMENT TO THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

Amendment of section 42 of Act No.32 of 2012.

24. In section 42 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, for the figures and letters “376A, 376C, 376D”, the figures and letters “376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB” shall be substituted.

RAM NATH KOVIND,
President.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2018.

MGIPMRND—167GI(S3)—21-04-2018

④

28/06